

प्रेषक,

विनीता कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण विभाग,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: जनवरी:21 2008

विषय :समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करने हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:599/XXII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई 2007 तथा शासनादेश संख्या: 1044/XXVII(1)/2007, दिनांक 04 दिसम्बर 2007(प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में समाज कल्याण के अंतर्गत अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु रु0. 4,10,00,000.00(रुपया चार करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नियंत्रण पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय क्षहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेंजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कौशल्यों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय।
3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के वॉल्यूम-5 के पार्ट-1 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका वॉल्यूम-1 के अन्तर्गत उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान

संख्या-15 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करने की धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अवचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त घालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराये।
11. बी०एम०-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष तथा आयोजनागत पक्ष में संलग्न तालिकाओं में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
13. बी०एम०-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के "अनुदान संख्या-15 में आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-00-800-अन्य व्यय-91-अकल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति-00-"के मानक मद 21-"छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन"" तथा "अन्य व्यय"के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या: 854(P)/xxvii(3)/07, दिनांक 15.01.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या ५७/XVII(1)-3/08-7(11) 2007, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कौषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कौषाधिकारी, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
9. वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से  
  
(धीरेन्द्र सिंह दताल)  
उपसचिव।